works under the Yojana can be taken up for execution at any time during the year i.e. whenever the need for generating employment is felt. They should preferably be started during lean periods and may continue during the busy agricultural periods too, if felt necessary.

Programmes for the Rural Poor

2793. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the various programmes undertaken by Government for the rural poor; and

(b) what is the progress made in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Integrated Rural Development Programme (IRDP) and Jawahar Rozgar Yojana (JRY) are the two major poverty alleviation programmes for the rural poor. IRDP aims at creation of self-employment for families below the poverty line in rural areas by providing productive assets and inputs to the target groups through the instrument of subsidy and bank credit. JRY aims to generate additional grainful employment for the unemployed and under-employed persons in the rural areas, both men and women, by creating wage-employment opportunities.

(b) The progress achieved in respect of the above programmes during the last two years is as under:-

Programme	Physical Target 1990-91	1991-92	Achievements 1990-91	1991-92
1. Integrated Rural Development Programme (IRDP) (No. of families assisted in million)	2.37	2.25	2.90	2.54
2. Jawahar Rozgar Yojana (JRY) (No of mandays generated in million)	929.10	735.44	874.56	808.10

National and State Council for Rural Agencies

2794. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to create the National and State Council for rural voluntary agencies and to formulate code of conduct for these agencies; and

(b) if so, the details and the objectives thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) There is no such proposal under consideration.

(b) Does not arise.

किसानों के लिए वैज्ञानिक-भंडारण की सुविधाएं

2795. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे किसानों को विशेषकर तथा ग्रामीण स्तर पर सीमान्त किसानों को वैज्ञानिक-भंडारण की सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार ऐसे कितने गोदाम स्थापित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख) कृषि स्तर पर वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1979-80 से ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों की स्थापना के लिए एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:- कटाई के तुरन्त बाद खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की घाटे की बिक्री को रोकना, घटिया किस्म के भण्डारण की वजह से मात्रा और गुणवत्ता में होने वाली हानियों को कम करना और कटाई के तत्काल बाद की अवधि में बाजार भण्डारण सुविधाओं और परिवहन पर पड़ने वाले दबाव को कम करना तथा किसानों को कृषि में काम आने वाले कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करना। केन्द्र सरकार इन गोदामों के निर्माण हेतु सबसिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1993-94 की केन्द्रीय वार्षिक योजना से इस योजना को हटा दिया है और अब यह राज्यों की वार्षिक योजना का हिस्सा होगी।

(ग) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे गोदामों की स्वीकृति नहीं दी गई थी। तथापि, इस योजना के प्रारम्भ होने के बाद 528 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार 528 गोदामों में से 425 गोदामों का निर्माण किया जा चुका है और बाकी गोदामों के निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेय जल मिशन

2796. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेयजल मिशन स्कीम शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इस मिशन के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसकी जिला-वार वास्तविक रूप से कितनी प्राप्ति हुई;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इन गांवों को शामिल करने के लिए पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित/प्रदान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी हां। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत आगरा, मिर्जापुर, सुलतानपुर और उन्नाव के मिनी-मिशन जिलों में पेयजल सप्लाई योजनाएं शुरु की गई हैं, फ्लोराइड कम करने, पानी से लौह को दूर करने के संयंत्र लगाए गए हैं और जल एकत्रीकरण ढांचों का निर्माण किया गया था।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त-उपलब्धियों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिये लक्ष्य वार्षिक योजना परिव्ययों में वर्ष दर वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य सभी ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराना है।

(घ) 1991-92 में उत्तर प्रदेश सरकार को रिलीज की गई निधियों और उनके प्रयोजनों को विवरण - 2 में दर्शाया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां

	योजना का नाम	कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या	गत 3 वर्षों के दौरान कवर किए गए गांवों की संख्या
1.	मिनी मिशन		
	आगरा	77	33
	मिर्जापुर	1245	1245
	सुलतानपुर	193	148
	उन्नाव	35	35
2.	उप-मिशन	अनुमोदित संयंत्रों की संख्या	अभी तक शुरु किए गए संयंत्रों की संख्या